**दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता**

*129. श्री राम जेठमलानी :
सरदार अजीत सिंह अरोड़ा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में उत्तरोत्तर कमी हुई है,

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1950-51 में दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी थी और वर्ष 1988-89 में इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में दालों की खपत देखते हुए दालों के आयात पर व्यय की जाने वाली राशि वर्ष 1990-91 में 500 करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है, और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम बनाया है और यदि हां, तो इस संबंध में लक्ष्य क्या है और उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) जी, हां। वर्ष 1989 को छोड़कर जबकि 1988 के 33 1 ग्राम से बढ़कर प्रति व्यक्ति प्रति दिन उपलब्धि 40 4 ग्राम हुई थी।

(ख) 1951 में दालों की प्रति व्यक्ति प्रति दिन उपलब्धि 60 7 ग्राम और 1989 में 40 4 ग्राम थी।

(ग) 1990 में अप्रैल से सितम्बर तक की अवधि के लिए आयात अनुमानत 3 63 लाख मीटरी टन अस्थायी रूप से रहा है जिसका मूल्य 219 86 करोड़ रहा है। चालू वर्ष के दौरान आयात का सावधानीपूर्वक मानिटर किया जा रहा है और दालों के देशी उत्पादन को ध्यान में रखते हुए आयात किया जायेगा।

(घ) दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं,

.1 राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना

2 विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम —दलहन

योजना में एक दोहरे दृष्टिकोण को अपनाये जाने की व्यवस्था है :

(1) बहुसस्य पद्धति के माध्यम से क्षेत्र में वृद्धि करना, और

(2) प्रति इकाई क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि करना। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत कृषकों को बीजों के लिए सहायता देने, मिनिकिटों का वितरण करने, प्रदर्शनों का आयोजन और पौध रक्षण उपाय अपनाने की व्यवस्था है। जुलाई, 1990 में सरकार ने दालों को प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया ताकि तीव्रता से और केन्द्रित रूप में विकास प्राप्त किया जा सके। 1990-91 के लिए 150 लाख मीटरी टन (खरीफ 55 और रबी 95 लाख मीटरी टन) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

**Strengthening of the Public Distribution System**

*130 SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL:

SHRI GHUFRAN AZAM.

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state

(a) whether Government have recently decided to take steps to strengthen the Public Distribution System in the country,

(b) if so, the details of the steps taken to strengthen the Public Distribution System in the country so far,

(c) whether instructions have been issued to State Governments to follow the guidelines for strengthening the Public Distribution System

(d) if so, the details of the guidelines/instructions issued by Government in this regard; and

(e) to what extent it would stabilise the prices of all essential commodities?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAO BIRENDRA SINGH): (a) to (d) The strengthening and streamlining of the Public Distribution System is a continual process. The Central Government has advised the State Governments/U T Administrations from time to time among other things, (i) to increase the coverage of population by opening of new Fair Price Shops (FPS) or using mobile vans in the areas which are unserved or underserved, (ii) to increase the commodity coverage; (iii) to evolve an effective coordination system among various agencies engaged in PDS; (iv) to organise sale of PDS items in haats in Tribal areas; (v) to set up advisory/Vigilance Committees at various levels; (vi) to monitor the availability of PDS items to consumers at field levels and (vii) to enforce strictly the provisions of Essential Commodities Act and similar other legislation to curb malpractices.

(e) Provision of essential commodities to the entire country through PDS at more or less stable prices has a significantly anti-inflationary effect

**Scrapping of the Haldia Fertilizer Project**

*131 SHRI P. K. KUNJACHEN Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) who were involved in the finalisation of the Hindustan Fertilizer Corporation's Rs 550 crorres Haldia Fertilizer Project now to be scrapped. been fixed on any one of them for dereliction of duty and squandering public money and for sabotaging developmental process, and

(b) whether any responsibility and squandering public money and for sabotaging developmental process; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPTT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI RAM BAHADUR SINGH): (a) The Haldia fertilizer Project was formulated by the Fertilizer Corporation of India and approved by the Government No decision has been taken to scrap the project.

(b) and (c) Do not arise

**Pollution due to rice production**

*132 SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that rice cultivation in the country is creating more pollution at present.

(b) if so, whether Government have analysed the reasons thereof and if so, the details thereof; and

(c) the steps Government propose to take to check without pollution affecting the production of rice,

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF AGRICULTURE AND TOURISM (SHRI DEVI LAL): (a) Sir, there is presently no experimental evidence to show that rice cultivation increases pollution.

(b) and (c) Does not arise

**दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों को नियमित किया जाना**

*133 **श्रीमती सूर्यकांता पाटील :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों के निवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सरकार को हाल ही में एक अभ्यावेदन दिया है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि दिसम्बर, 1990 तक बसायी गयी कालोनियों को नियमित किया जाये ;